ces. I myself have declared it in Bombay. And we have given it to the State of Maharashtra. There is no question of waiting for the Central assistance by the State, by any State. And so far as Maharashtra is concerned, we have given more money compared to other States.

SHRI S. W. DHABE: Is Rs. 87.24 crores more?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I have already quoted the example. If the hon. Member wants, now let me tell you, let me inform you who is responsible for the situation. Let us examine it. It is the State Government who is not implementing.. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If you had merely said, "We have given the money," nobody would have objected. You said "more". Therefore, they are on their legs. Please go ahead.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, we have given the amount. We are considering the case of Maharashtra also for relaxing the standards of norms in the case of drought.

*185. [The questioners (Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare and Dr. Lokesh Chandra) were absent. for answer vide cols. 39-40 infra.]

बाढ़ तथा चक्रवात से प्रभावित कृषि भूमि

*186. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
श्री अश्विनी कुमार :†

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र में बाढ़ों और चक्रवातों से प्रतिवर्ष औसतन कितनी-कितनी कृषि भूमि प्रभावित होती है और इसके परिणाम-स्वरूप औसतन-कितनी-कितनी हानि होती है ; और

(ख) बाढ़ और चक्रवात से प्रभावित इन क्षेत्रों में से किन-किन क्षेत्रों को अब तक फसल योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एक विवरण (अनुबंध-I और II) सभा पटल पर रखा जाता है ।

*सभा में यह प्रश्न श्री अश्विनी कुमार द्वारा पूछा गया ।

विवरण–I

राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में 1953–85 की अवधि के दौरान बाढ़ तथा चक्रवात से प्रभावित औसत फसलगत क्षेत्र तथा औसत क्षति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1953–85 की अवधि के दौरान वार्षिक तौर पर क्षतिग्रस्त औसत फसल गत क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	1983–85 की अवधि के दौरान फसल को हुई औसत वार्षिक क्षति (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.1	5352.7
2.	असम	1.7	1050.2
3.	बिहार	6.4	4087.4

1	2	3	4
4.	गुजरात	2.7	1372.3
5.	हरियाणा	1.7	901.2
6.	हिमाचल प्रदेश	0.3	606.5
7.	जम्मू और कश्मीर	0.1	29.9
8.	कर्नाटक	1.0	51.1
9.	केरल	0.3	865.2
10.	मध्य प्रदेश	1.9	424.9
11.	महाराष्ट्र	0.7	302.7
12.	मणिपुर	0.1	80.1
13.	मेघालय	0.08	141.7
14.	नागालैंड	0.01	14.3
15.	उड़ीसा	3.2	1316.1
16.	पंजाब	1.4	737.3
17.	राजस्थान	2.6	1203.7
18.	सिक्किम	0.08	307.8
19.	तमिलनाडु	3.1	1140.2
20.	त्रिपुरा	0.1	191.4
21.	उत्तर प्रदेश	13.9	13702.0
22.	पश्चिमी बंगाल	2.9	3414.3
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नगण्य	0.1
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.005	10.25
25.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य
26.	दादरा व नागर हवेली	नगण्य	0.3
27.	दिल्ली	0.06	77.5
28.	गोवा, दमन और दीव	0.002	0.4
29.	लक्षद्वीप	नगण्य	1.5
30.	मिजोरम	0.0023	2.9
31.	पांडिचेरी	0.04	99.2
	भारत	40.7	31667.4

विवरण–II

1985 के खरीफ मौसम में शुरू हुई व्यापक फसल बीमा स्कीम को क्रियान्वित करने वाले राज्यों के नाम

क्रम सं०	राज्य का नाम	शामिल किये गये जिलों की संख्या	शामिल किये गये तालुकों की संख्या	फसल का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	133	धान
		9	50	मूंगफली
		13	60	ज्वार
2.	गुजरात	17	98	मूंगफली
		8	46	धान
		16	71	बाजरा
3.	बिहार	29	..	शरदकालीन धान
4.	हरियाणा	9	30	चावल
		7	23	मक्का
		11	38	बाजरा
5.	हिमाचल प्रदेश	5	10	चावल
		7	18	मक्का
6.	कर्नाटक	12	75	ज्वार
		11	81	मूंगफली
		15	102	धान
		8	64	रागी
7.	केरल	11	53	शरदकालीन धान
8.	महाराष्ट्र	26	170	चावल
		21	156	ज्वार
		21	141	मूंगफली
		13	88	बाजरा
		16	70	तुर
9.	मध्य प्रदेश	26	91	ज्वार
		16	42	धान
10.	उड़ीसा	13	311 (ब्लाक)	धान
11.	तमिलनाडु	15	148	धान
		12	48	मूंगफली (अधिसूचित)
12.	उत्तर प्रदेश	12	24	मक्का
		41	177	मूंगफली
13.	पश्चिमी बंगाल	16	241 (पुलिस स्टेशन क्षेत्र)	धान

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर दिया गया है उसमें 1953 से 85 तक औसत स्टेट्स में कितनी फसल बर्बाद होती रही है इसका एक अनुमान है और कितना प्रतिवर्ष उसके ऊपर नुकसान होता रहा है इसका भी एक अनुमान है । इस अनुमान से बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अगर दो स्टेट्स बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर देखें तो आधे से ज्यादा नुकसान इनका हो रहा है । कैशवाइज जो 316 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है उसमें आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों स्टेट्स को मिला कर 240 करोड़ का नुकसान हो रहा है यानी 3/4 । मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह जो तीन महत्व के स्टेट्स हैं जहां पर इतना डैमेज हो रहा है उनको ठीक करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? और क्या उसके लिए कोई सैन्ट्रल स्कीम है या सैन्ट्रल असिस्टेंस है और या केवल प्रदेशों पर ही छोड़ दिया है ? अगर कोई सेन्ट्रल स्कीम है तो उसका क्या विवरण है वह हमको बताने की कृपा करें ?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, for the last 30 years measures have been taken to control floods, to avoid and minimise the flood damages, and various activities were taken up by the States with the assistance of the Centre. I can say that up to 1980 and in the Sixth Plan period what we have achieved is:

The length of the embankments constructed is 12,045 km. up to 1980, and during 1980-85, during the Sixth Plan period, the length is 2,117 km.

The length of the drainage channel constructed up to March, 1980 is 21,868 km. and during the Sixth Plan period it is 4,251 km.

The towns protected are 304 up to March, 1980 and 71 during the Sixth Plan period.

The number of villages raised are 4,696 up to March, 1980.

The expenditure insurred up to March, 1980 is Rs. 975.9 crores, and during the Sixth Plan period it is Rs. 766.7 crores. The total by the end of the Sixth Plan is Rs. 1,742.6 crores. Besides this, the total area protected from the floods upto March 1980 is 112.12 lakh hectares and during the Sixth Plan period it was 17.94 lakh hectares.

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बहुत सारे आंकड़े दिये हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहता हूं कि बिहार के किन किन टाउन्स में आपने यह काम किया है उसकी सूचना दे दें तो बड़ी कृपा होगी . . . (व्यवधान) । इसकी सूचना आप बाद में दे दें। दूसरे मैं इस विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि आपने क्रॉप इंश्योरेन्स की योजना शुरू की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में कितने ताल्लुको में आपने यह क्रोप इंश्योरेन्स की स्कीम चालू की है ? आपने बिहार के अन्दर 29 जिलों के नाम तो दिये हैं, लेकिन आपने कितने ताल्लुकों को कवर किया है, यह नहीं बताया है । क्या आप इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे क्योंकि जिलों के नाम तो आपने लिख दिये हैं लेकिन आपकी यह योजना ताल्लुकों और ब्लाक्स में नहीं पहुंची है ? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने फ्लड एफैक्टेड एरियाज के लिए गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड बनाया है, लेकिन बिहार के अन्दर बक्सर से लेकर फरक्का तक जो सबसे बड़ा फ्लड एरिया है उसके लिए क्या आपने कोई खास योजना बनाई है ? यह जो गंगा दियारा का क्षेत्र कहलाता है, क्या आप इसके लिए बिहार में कोई विशेष गंगा दियारा बोर्ड बनाएंगे क्योंकि अब इसकी मांग भी उठने लगी है ? क्या गंगा दियारा के लिए अलग से कोई बोर्ड बनाएंगे ? मेरा पहला प्रश्न यह

है कि आपकी योजना ब्लाक्स तक नहीं पहुंची है, यह अभी कलेक्टर के घर तक ही पहुंच पाई है। उसके संबंध में आप स्पष्ट उत्तर दे दें।

SHRI B. SHANKARANAND: It is true that in the list there has not been any number indicated in the column of numbers covered of Talukas. It is a fact that as far as Bihar is concerned only districts have been shown. I do not know why, but that is also the information that has been given to me.

MR. CHAIRMAN: You may send the information to the hon. Member.

SHRI B. SHANKARANAND: Yes, I will.

In regard to the other part of his question, I may inform the hon Member that the Ganga Flood Control Board is there and it is taking action as far as the demands indicated by the hon. Member are concerned.

MR. CHAIRMAN: What about the crop insurance?

SHRI B. SHANKARANAD: This is with reference to the crop insurance.

MR. CHAIRMAN: No. He said in Bihar only a number of districts has been mentioned.

SHRI B. SHANKARANAND: That is what I said. Twentynine districts have been mentioned. The number of Talukas has been mentioned. I will find it out and furnish the information to the Hon. Member.

श्री रामचन्द्र विकल : माननीय मंत्री जी ने बताया कि बाढ़ के कारण बिहार और यू० पी० आदि प्रान्तों में काफी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फसल बीमा भी शुरू किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फसल बीमा से जिलों में कितने किसान प्रभावित हुए हैं और इस योजना से प्रभावित किसानों को तादाद कितना है ? आपने यह फसल बीमा योजना तो जरूर शुरू की है, लेकिन इसका किसानों पर कितना असर हुआ है, यह बताने की कृपा की जाये ? आपने यह योजना कब से शुरू की है और कितने क्षेत्रों में किसानों को इसका लाभ पहुंचा है ?

SHRI B. SHANKARANAND: The crop insurance scheme has been started from the Kharif season of 1985. I have got the figures as to the total number of farmers covered, the area covered in hectares, the total sum insured in crores of rupees and the total insurance charges. I have got a long list. If the hon. Member wants it I can read it out here or I can furnish the information to him.

MR. CHAIRMAN: You send the list to the Members who want it.

SHRI V. NARAYANASWAMY: Our State, Pondicherry, had drought in the middle of 1985 and flood at the end of 1985. About forty thousand families have been affected and fifty thousand acres of land was completely flooded. We have written to the Central Government for relief assistance and the Hon. Minister of Agriculture visited our State. We claimed a relief of Rs. 12 crores, but the Government granted Rs. 5/- crores for the purpose of development measures. The Prime Minister also visited our State. In this background, I would like to know whether the Central Government proposes to give subsidy relating to the foodgrains—wheat or rice—to the affected areas till such time the relief work is completed there.

SHRI B. SHANKARANAND: As far as the hon. Members's question is concerned, it relates to the drought situation. But we are discussing the question of floods and cyclone which affected agricultural land.

SHRI V. NARAYANASWAMY: My question relates to floods also.

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, I have got with me figures for Pondicherry. The Central assistance given to Pondicherry durring 1983-84 and 1984-1985 with regard to floods and other natural calamities excluding

drought is Rs. 1.29 crores and Rs. 0.17 crores respectively.

SHRI BISWA GOSWAMI: Sir, Assam is a State where every year floods occur three or four times. I am surprised to see from the statement (Annexure I and II) that Assam has been totally left out from the crop insurance scheme. I do not know why this step-motherly attitude has been shown in the case of Assam for not its inclusion under the crop insurance scheme. I want to know about this from the Minister.

I also understand that a master plan is being prepared by the Brahmaputra Flood Control Board. I want to know what is the progress of that so-called master plan. What concrete measures the Government of India has taken to control the Brahmaputra river and what other flood control measures are taken in the State of Assam?

SHRI B. SHANKARANAND: As far as the flood control of Brahamaputra the mighty river in this country is concerned, there is a special Board for it and entire money is borne by the Government of India and that Board is drawing a master plan for the entire river. I think the master plan is almost ready. As soon as we get it further action will be taken in that regard.

As far as the State of Assam is concerned, the crop insurance scheme is administered by the State Government and the General Insurance Company. But so far the Assam Government has not come forward to administer the scheme. Since a new Government has been formed in the State of Assam—I hope that they will take up this scheme for the benefit of the farmers of that State.

श्री घनश्याम सिंह : सभापति महोदय, अभी तक काफी हानि चक्रवातों और बाढ़ से होती रही है । पर्टिक्यूलरली उत्तर प्रदेश में 13702 रुपये की हानि आपके आंकड़ों के अनुसार बताई गई है । आपने अभी माननीय सदस्यों के पूछने पर बताया कि बहुत बड़ी सूची है और वह भेजी जा सकती है पढ़ने में समय बरबाद होगा । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की हानि इस संबंध में 13703 लाख रुपये तक है तो जो फसल बीमा योजना आपने उत्तर प्रदेश में चलाई है उसमें :

ए—मक्का और मूंगफली के बाद और भी अन्य ऐसी फसलों को जिन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए था, उन्हें इसमें शामिल करने के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

बी—आपने उत्तर प्रदेश के 12 के 24 तालूकों में तथा 41 जिलों के 177 तालूकों में जो फसल बीमा योजना प्रारम्भ कराई है तो आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपने वहां कितने काश्तकारों का बीमा कराया और उनमें से कितने काश्तकारों को बीमा का क्लेम मिला और उन्हें कुल कितना अमाउन्ट मिला, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

SHRI B. SHANKARANAND: As far as Uttar Pradesh State is concerned, as the Brahmaputra is a mighty river, so also the Uttar Pradesh is a mighty State. Sir, the farmers covered under the scheme in Uttar Pradesh is 4,50,000; and the area covered in hectares is 4,75,000. The total sum insured Rs. 55 crores. This is as far as U. P. is concerned. The hon. friend is interested in knowing, besides groundnut and maize, if there are any other crops which have been insured. According to my information, all coarse grains, oilseeds and now fruits are proposed to be included in this scheme. I wish the Government of U. P. takes the benefit of this scheme for the welfare of the farmers.

MR. CHAIRMAN: Next question.